# पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 17, अंक 1/2016


## राजस्थान महापौर सम्मेलन

# पुरानी तकनीक तथा नवाचारों को अपनाना शहरी विकास की जरूरत!

'शहरी विकास के लिए आज जल प्रबन्धन, सफाई, कचरा प्रबन्धन एवं हरित शहर बनाने के लिए पुरानी तकनीक तथा नवाचारों को अपनाने की जरूरत है।'

उक्त विचार 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा 17 फरवरी, 2016 को राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग की सक्रिय भागीदारी में आयोजित 'राजस्थान महापौर सम्मेलन' में उभरकर सामने आए। सम्मेलन का आयोजन 'दि एशिया फाउण्डेशन' के सहयोग से 'सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म' परियोजना के तहत किया गया।

कार्यक्रम में पुरुषोत्तम बियानी, निदेशक व संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास की बहुत सी फ्लेगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।

उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, एनर्जी सेविंग के लिए एलईडी, स्मार्ट सिटी मिशन एवं ई-गवर्नेंस आदि योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं को लागू करने में प्रारम्भिक स्तर पर कुछ स्थानीय समस्याएं आ सकती है, किंतु इनका आपसी बातचीत व जन सहभागिता से समाधान किया जा सकता है।

निर्मल नाहटा, महापौर जयपुर ने जयपुर शहर में परिवहन एवं यातायात और अन्य समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समस्याओं के समाधान में जन भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने जयपुर शहर में पोड कार चलाने, ग्रीन रूफ टॉप गार्डन को बढ़ावा देने व स्मार्ट कार्ड जैसी कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के सभी वार्डों में वार्ड कार्यालय बनाने की भी योजना है। इन वार्ड कार्यालयों में स्थानीय निवासियों को निगम द्वारा सभी प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी।

धर्मेन्द्र गहलोत, महापौर अजमेर ने कहा कि अजमेर नगर निगम ने सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबन्धन व डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण योजना पर जोर दिया। भरतपुर महापौर शिव सिंह भौंट ने कॉलोनियों के नियमन संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वित्तीय समस्या के कारण निगम की कई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। बून्दी के सभापति ने बताया कि शहर में सार्वजनिक दीवारों व खम्भों पर जन सहभागिता के माध्यम से पेंटिग करवाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया है। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के सभापति ने सुनहरे चित्तौड़ योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी।

कार्यक्रम में जॉर्ज चेरियन, निदेशक 'कट्स' ने जयपुर नगर निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए देश में 29वां स्थान प्राप्त करने पर निगम को बधाई दी। मीशा टंडन सीनियर मैनेजर 'आईसीएलईआई', नई दिल्ली ने किशनगढ़ और जैसलमेर में जल प्रबन्धन पर पुरानी तकनीक पर हो रहे कार्य पर प्रकाश डाला। हिमानी तिवारी, समन्वयक सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दी तथा स्वायत शासन विभाग व 'कट्स' के मध्य सिटी मैनेजर की क्षमतावर्धन हेतु सहमति-पत्र पर किए गए हस्ताक्षर के बारे में बताया।

सम्मेलन के प्रारंभ में अमर दीप सिंह, परियोजना समन्वयक ने परियोजना के उद्देश्यों एवं प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि यह तीसरा महापौर सम्मेलन है, जिसमें राज्य के महापौर व उप-महापौर के अतिरिक्त स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

### इस अंक में...


- गरीबों का गेहूं खा गए अफसर ............ 3
- 'मेक इन इंडिया' की धीमी रफ्तार .......... 4
- भ्रष्टाचार: सिर्फ रैंकिंग ही सुधरी, हम नहीं ... 5
- जरूरी है न्यायिक प्रणाली में सुधार .......... 7
- जल स्वावलम्बन अभियान में जुटें .......... 9

### विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

# एंटीबायोटिक के बारे में हों जागरूक

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर 'कट्स' द्वारा जयपुर में 'प्रतिजैविक पदार्थों से मुक्त भोजन' विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के प्रोफेसर डॉ. निर्मल के. गुरवानी ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं की अधिकता के बारे में उपभोक्ता एवं कंपनी दोनों को जागरूक होना होगा। इनके ज्यादा उपयोग से मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और शरीर में मौजूद मित्र वायरस धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अशोक गुप्ता ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाइयां मरीज को उसकी जरूरत के हिसाब से ही लिखी जानी चाहिए।

कार्यशाला में उपभोक्ता विभाग के उप निदेशक संजय झाला ने कहा कि भारत में एंटीबायोटिक दवाइयों के अधिक उपयोग से हो रहे शारीरिक और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना आवश्यक है। राजस्थान विश्वविद्यालय की होम साइंस विभाग की प्रोफेसर डॉ. कनिका वर्मा ने बताया कि पशुओं में होने वाली बीमारियों के इलाज में भी एंटीबायोटिक दवाएं काम में ली जा रही है। दिल्ली व एन.सी.आर. में बिकने वाले चिकन में 40 प्रतिशत तक एंटीबायोटिक की मात्रा पाई गई है। गुवाहाटी से लिए गए दूध के नमूनों में भी 33 प्रतिशत तक एंटीबायोटिक मिला है। इस पर निगरानी होना आवश्यक है।

'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने स्वागत सम्बोधन में बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार एंटीबायोटिक के अन्धाधुंध प्रयोग के कारण विश्व में दो अरब लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि बहुराष्ट्रीय फूड चेन कंपनियां भी एंटीबायोटिक के उपयोग नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हों।

कार्यशाला में उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, उपभोक्ता संस्थाओं व मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

# राजस्थान में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार पर चर्चा

प्रदेश में बिजली प्रबन्धन को बेहतर बनाने, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए जयपुर डिस्कॉम एवं 'कट्स' के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन दिनांक 22 फरवरी, 2016 को विद्युत भवन के सभागार में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने की।

कार्यशाला में, जयपुर विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी, विभिन्न जन संगठन, उपभोक्ता संगठन एवं कृषि वर्ग के संगठनों ने भाग लिया एवं विद्युत कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए अलग-अलग सुझाव दिए। जिनमें प्रमुख रूप से विद्युत कंपनी द्वारा राजस्व प्राप्ति हेतु नए रैवॅन्यू कलेक्शन सेंटर खोलना, खराब पड़े हुए विद्युत मीटरों को तुरंत बदलना, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देना, विद्युत चोरी एवं छीजत को रोकने के लिए कारगर कदम उठाना एवं बिजली कटौती के संबंध में उपभोक्ताओं को कटौती से पूर्व सूचना देना है। कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के ट्रांसफॉर्मर जलने पर उन्हें तुरंत बदलने के मामले को किसान संगठनों ने जोरदार ढंग से रखा। इसके अलावा कार्यशाला में कई सुझाव और भी उभर कर आए, जिनमें से कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हैं:

- जो मीटर उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें तुरंत बदले तथा उन्हें वापिस निर्माता कंपनियों को दें।
- नागरिकों को पूर्व सूचना के बिना बिजली कटौती नहीं हो। इस हेतु कम से कम दो-तीन दिन पूर्व सूचना दें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर जलने पर उन्हें तुरंत बदले।
- मीटर पठन, बिल जारी करना तथा राशि संग्रहण के कार्य विद्युत विभाग के सदस्यों द्वारा किया जाए।
- बिजली चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।



सही योजना उचित कदम! सुशासन का यह है धर्म !!

### कृषि विकास कार्यों में लापरवाही

प्रदेश में कृषि व पशुपालन के विकास कार्यों के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले धन में से अभी तक सिर्फ 34 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पाई है। प्रदेश के कृषि व पशुपालन विकास के लिए करीब 1768 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए थे, जिसमें से अभी तक राज्य सरकार ने 594 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। जबकि वित्त विभाग से कृषि विभाग को 719 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं।

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने समीक्षा बैठक के दौरान आवंटित बजट को खर्च नहीं करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि 31 मार्च तक आवंटित बजट को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया जाना चाहिए।

*(दै.न., 02.02.16)*

### इंदिरा आवास योजना में ढिलाई

इंदिरा आवास योजना में कई जिलों को दिल खोलकर राशि आवंटन के बाद भी योजना के हाल 'ढाक के तीन पात' बने हुए हैं। वित्तीय सत्र के प्रारंभ में ही राशि आवंटन कराने के बाद भी लक्ष्य में पिछड़े कुछ जिलों में भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि बिना खर्च किए ही पड़ी है। केन्द्र व राज्य सरकार की योजना के तहत आवास निर्माण प्रक्रिया पूरी कर सभी को आवास मुहैया कराने की मंशा है।

वित्तीय सत्र समाप्ति के नजदीक आने पर बजट लैप्स का खतरा देखते हुए विभाग ने इन जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इनमें उदयपुर सहित छह जिलों की गंभीर लापरवाही बनी हुई है। इंदिरा आवास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना होने के कारण बजट राशि का हिसाब केन्द्र सरकार को भी देना पड़ता है। *(दै.न., 08.02.16)*

### जल स्वावलंबन में करोड़ों की गड़बड़ी

जल स्वावलंबन अभियान में धरातल पर काम शुरू होने से पहले ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इस गड़बड़ी का खुलासा जीपीएस के जरिए मौका निरीक्षण से हुआ है। प्रोजेक्ट लागू कर रहे वाटरशेड डायरेक्टर अनुराग भारद्वाज ने बताया कि इसमें लापरवाही और मिलीभगत दोनों ही तरह के मामले सामने आए हैं।

ज्यादातर मामलों में गड़बड़ियां इसलिए हुई क्योंकि अभियान से जुड़े इंजीनियर स्ट्रक्चरों के लिए नाप-जोख करने मौके पर गए ही नहीं और गाड़ी में बैठे-बैठे ही जहां छोटे निर्माण किए जाने थे वहां बड़े चैक डैम एनिकट बनाने के नक्शे बनाकर प्रस्ताव तैयार कर भिजवा दिए। इनमें कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां पहले से निर्माण हो रखे थे और पैसा उठाने के लिए उन जगहों पर निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर भेज दिए गए।

*(दै.भा., 27.02.16)*

### कंपनियों ने लगाया सरकार को चूना

देश की छह टेलीकॉम कंपनियों ने कई जगहों पर अपनी कमाई कम दिखाई। इससे सरकार को 12 हजार 489 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी-कैग) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। यह रिपोर्ट संसद में रखी गई है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2006 से 2010 के दौरान इन कंपनियों ने अपनी कमाई (एजीआर) 46,045.75 करोड़ रुपए कम दिखाई।

दूरसंचार विभाग की खिंचाई करते हुए कैग ने कहा 'रैवेन्यू शेयरिंग' व्यवस्था लागू हुए 16 साल हो गए। इसके बावजूद डॉट यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कंसोलिडेटेड फंड में उचित और पूरा पैसा जाए। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी जाएगी तथा विभाग कंपनियों के खातों की स्पेशल ऑडिटिंग कराएगा। *(दै.भा., 12.03.16)*

### प्रदेश के मंत्रियों ने नहीं बताई संपत्ति

प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और केन्द्रीय व राज्यों के मंत्रियों के लिए हर साल अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने का नियम है। लेकिन पिछले तीन सत्रों से प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत किसी भी मंत्री ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। जबकि पूरी केबिनेट को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर हर साल जनवरी में अपनी संपत्ति की घोषणा करने का प्रावधान है, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की संपत्ति की सूचना शून्य दर्शाई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ज्यादातर केन्द्रीय मंत्रियों की ओर से तय सीमा के भीतर हर साल संपत्ति की घोषणा की जा रही है तथा केन्द्रीय मंत्रीमंडल के सदस्यों की संपत्ति का ब्योरा केन्द्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

*(दै.भा., 03.02.16)*

## गरीबों का गेहूं खा गए अफसर

अब तक सुना था कि गेहूं को घुन खाता है, लेकिन इसकी रक्षा के लिए बने फूड कॉर्पोरेशन और रसद विभाग के अधिकारी तो इस छोटे से कीड़े से भी खतरनाक निकले। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये ऐसा गेहूं खा गए, जो कहीं था ही नहीं। कागजों में ही गेहूं खरीदा, कागजों में ही गोदामों तक पहुंचाया और कागजों में ही गरीबों को बांट दिया। पूरा 3.50 लाख क्विंटल गेहूं चट कर गए... और कर दिया 50 करोड़ रुपए का घोटाला।

यह घोटाला अलवर व भरतपुर में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अफसरों, रसद विभाग के डीएसओ और मंडियों के आढ़तियों ने मिलकर किया। अप्रेल से जून 2015 के बीच हुए इस महाघोटाले की अब तक चार बार जांच हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। रिपोर्ट के मुताबिक आढ़तियों के माध्यम से जिन किसानों से गेहूं खरीदना बताया, हकीकत में किसान थे ही नहीं। आढ़तियों ने किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिए। उन्हीं के नाम पर भुगतान के चैक काटे गए। डीएसओ ने फर्जी राशन कार्ड पर गेहूं बांटा। बाद में यह पैसा एफसीआई के अफसरों, डीएसओ और आढ़तियों तक पहुंच गया। *(दै.भा., 30.03.16)*

## 'मेक इन इंडिया' की धीमी रफ्तार

देश के प्रमुख उद्योग मण्डल 'एसोचैम' के राष्ट्रीय महासचिव डी.एस.रावत ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने भारत को दुनिया का प्रमुख निर्माण हब बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' की परिकल्पना पेश की है, लेकिन देश में आने वाले निवेश की परियोजनाओं के तौर पर अमल में आने की मौजूदा धीमी रफ्तार के कारण जाहिर की गई परिकल्पना की उम्मीदें अपनी चमक खो रही हैं।

उन्होंने कहा कि देश में निवेश की घोषणाएं तो हो रही हैं, लेकिन वे जमीन पर नहीं उतर रही। इसके अलावा जो निवेश हो चुका है उससे जुड़ी परियोजनाओं के मुकम्मल होने में लग रही देर के कारण लागत में बढ़ोतरी होने से निवेशकों का विश्वास और इरादा दोनों ही कमजोर हो रहे हैं। *(न.दु., 24.02.16)*

### ग्रामीण विकासः नहीं हुआ पैसा खर्च

ग्रामीण विकास की नौ योजनाओं में पिछले नौ महीनों में बजट का महज 47 फीसदी पैसा ही खर्च हुआ है। वित्त वर्ष खत्म होने में बचे तीन महीने में योजनाओं का 53 फीसदी बजट खर्च होना बाकी है। बजट खर्च के लेटलतीफी आंकड़ों में सभी संभागों के जिले पिछड़े हुए हैं। विभाग के बार-बार रिमाइंडर के बाद भी योजनाओं में फिसड्डी साबित होने पर अब अफसरों को फिर से चेताया गया है।

ग्रामीण विकास की योजनाओं में इस साल 2011 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। इस बजट में से दिसम्बर तक 948 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इस वित्त वर्ष के तीन महीने बचे हैं और योजनाओं का 1062 करोड़ रुपया बिना खर्च किए पड़ा है।

*(दै.न., 25.01.16)*

### आयकर विभाग ने की गलतियां

राजस्थान में आयकर अधिकारियों का वित्त वर्ष 2014-15 में कर आकलन में 1056.67 करोड़ रुपए की गलतियां करने का मामला सामने आया है।

यह खुलासा हाल ही में संसद में पेश की गई भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट में हुआ है। यदि देशभर की बात की जाए तो गलतियां 19077.72 करोड़ रुपए की है।

रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 में अंकेक्षण के दौरान 13236 आकलनों की जांच की गई। इसमें सामने आया कि हर सौ आकलन में से छह से ज्यादा में गलतियां की गई है। कहीं बेवजह छूट दे दी गई तो कहीं जुर्माना वसूली योग्य होने पर भी नहीं वसूला गया। कई मामलों में तो कर का आकलन ही कम किया गया। *(रा.प., 18.03.16)*

### सरकारी खजाने को करोड़ों की हानि

राज्य में वर्ष 2014-15 में नौकरशाही की गलती से 346.48 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली नहीं हुई। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) ने अपने प्रतिवेदन में यह खुलासा किया है। सीएजी की ओर से 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के तैयार इस प्रतिवेदन को विधानसभा में पेश किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार खासतौर से वाणिज्यिक विभाग, आबकारी विभाग, खान विभाग और परिवहन विभाग में करोड़ों रुपए की वसूली नहीं होने से सरकारी खजाने को चपत लगी है। इसके अलावा मुद्रांक कर की वसूली में भी अनियमितता सामने आई है। करीब सात सौ ओवरलोड वाहनों के मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से करीब दो करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई। *(रा.प.एवं दै.न., 30.03.16)*

### अधिकारियों ने बेच खाये ट्रांसफॉर्मर

विद्युत निगम में अच्छे भले ट्रांसफॉर्मरों को खराब बता कर उन्हें बेचने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे इस खेल में पहले ट्रांसफॉर्मरों की खराब व जले होने की रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके बाद उसकी जगह पर नया ट्रांसफॉरमर जारी कराया जाता है।

इसके बाद पुराने ट्रांसफॉर्मर को अवैध रूप से बेचकर पैसा कमाया जा रहा है। इसका खुलासा निगम की विजिलेंस जांच में हुआ। विजिलेंस टीम को जांच के दौरान कई गांवों में खेतों पर फर्जी ट्रांसफॉर्मर लगे मिले, जिनका उपभोक्ता के पास कोई प्रमाण नहीं पाया गया। नियमानुसार खराब ट्रांसफॉर्मर स्टोर में जमा कराना होता है। *(रा.प., 03.01.16)*

### नहीं बंट रहा फोर्टिफाइड आटा

प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए पांच प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त फोर्टिफाइड आटा उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री की घोषणा अधर में ही उलझकर रह गई। घोषणा पर अमल करने में सरकार की वित्तीय स्थिति भारी पड़ रही है। इस पर होने वाले सालाना 700 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार को देखते हुए सरकार अभी योजना को लागू करने का निर्णय नहीं ले पा रही है।

कहा जा रहा है कि गेहूं की पिसाई व आटे को फोर्टिफाइड करने में ढाई रुपए का खर्च आता है। इससे दो रुपए किलो दिए जा रहे गेहूं की बजाय आटे की कीमत साढ़े चार रुपए किलो बैठती है। गेहूं खरीदने वाले लोगों को यह बढ़ी कीमत देना मंजूर नहीं होगा। मद्देनजर फिलहाल इस योजना को लागू नहीं किया गया है। *(दै.भा., 28.02.16)*

### अमृत मिशन में खर्च किए 'जीरो'

अमृत मिशन के पहले फेज में 12 शहरों को शामिल करते हुए केन्द्र सरकार ने 934 करोड़ रुपए राज्य को मुहैया करवाए, लेकिन राज्य सरकार इस राशि में से एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकी। हालात यह है कि मिशन में शामिल 29 शहरों के अभी सिटी इम्प्रूवमेंट प्लान भी तैयार नहीं हो सके हैं।

स्वायत शासन विभाग ने मिशन में शामिल शहरों के संबंधित सभी निकायों को 15 मार्च तक किसी भी सूरत में प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इनमें से एक भी प्लान सरकार को नहीं मिल सका।

*(दै.न., 18.03.16)*

## कालाधन, नाम नहीं बताएगी सरकार

कालेधन को लेकर जमीन–आसमान एक करने का वादा कर सत्ता में आई एनडीए सरकार के अधिकारियों ने कालाधन घोषित करने वालों के नाम उजाकर करने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों का तर्क है कि स्वेच्छा से कालेधन की घोषणा करने वालों के नाम आरटीआई एक्ट के तहत तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना के दायरे में आते हैं और ये सार्वजनिक नहीं किए जा सकते।

सूचना के अधिकार के तहत चन्द्रशेखर गौड़ ने दिल्ली के आयकर आयुक्त के यहां आवेदन पेश कर जानकारी मांगी थी कि कालेधन की घोषणा करने वालों में कितने राजनेता, नौकरशाह और उनके परिवारजन शामिल है। उन्होंने आवेदन में उनके पद और नामों की जानकारी भी मांगी थी।

*(रा.प., 02.01.16)*

## भ्रष्टों की बनाएं 'सीक्रेट डायरी'

सरकार ने सुपरवाईजरी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने मातहत कर्मचारियों की गोपनीय डायरी संधारित करें। इसमें उनके कथित भ्रष्ट आचरण और उस पर की गई कार्रवाई दर्ज करें।

आमतौर पर देखा जाता था कि रिपोर्टिंग अधिकारी अपने मातहत अफसरों की ईमानदारी के बारे में स्पष्ट तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करते। इससे एनुअल परफॉरमेंस असेसमेंट रिपोर्टों (एपीएआर) में उसका कोई जिक्र नहीं होता। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि अब सुपरवाईजरी अफसर गोपनीय फाइलें संधारित करें और उनमें इस बारे में पूरा उल्लेख अंकित करें। *(दै.भा., 17.02.16)*

## एसीबी के जाल का खौफ

खान विभाग में महाघूसकांड के खुलासे के बाद रिश्वत लेने वालों की संख्या में कमी आई हैं। जयपुर में 20 से भी अधिक रिश्वत मांगने वाले लोगों ने पीड़ित को बिना राशि लिए लौटा दिया। इससे आधा दर्जन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एसीबी के चंगुल में आने से बच गए।

एसीबी अब ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर निगाह रखे हुए हैं। वर्तमान में रिश्वत मांगने के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें एसीबी सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई कर रही है। एसीबी के सूत्रों के मुताबिक, रिश्वतखोरों में एसीबी का खौफ इस कदर है कि वे रिश्वत के संबंध में फोन पर बातचीत करने से भी कतरा रहे हैं। रिश्वत देने वाला ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के यहां चक्कर लगा रहा है, लेकिन वह उनसे रुपए भी नहीं ले रहे। *(रा.प., 07.02.16)*

## अभियोजन स्वीकृति में देरी

प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा रंगे हुए नोटों के साथ पकड़े गए एवं पद के दुरुपयोग करने वाले आरोपियों के खिलाफ मांगी गई अभियोजन स्वीकृति देने में हो रही देरी से एसीबी की राह कठिन हो गई है। नियमानुसार तीन माह में मिलने वाली अभियोजन स्वीकृति अब कई सालों में भी नहीं मिल रही।

एसीबी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 04 दिसम्बर 2015 तक गृह विभाग (एचओडी) के 35 विभागों में 293 और कार्मिक विभाग (डीओपी) के 16 विभागों के 41 मामले अभियोजन स्वीकृति की बाट जोह रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जब तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती तब तक एसीबी की जांच आगे नहीं बढ़ सकती। *(दै.न., 04.01.16)*

## आरटीडीसी में 13 करोड़ का घोटाला

राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) की दो लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स और रॉयल राजस्थान में बुकिंग के नाम पर किए गए घोटाले का मामला कैग तक पहुंच गया है।

कैग की ओर से आपत्ति लगाई गई है कि आरटीडीसी ने जिस कंपनी से ट्रेनों की बुकिंग का अनुबंध किया था, उस कंपनी की ओर से 13.17 करोड़ रुपए की वसूली की जानी चाहिए थी। लेकिन आरटीडीसी द्वारा यह वसूली नहीं की गई है। जिस कंपनी को बुकिंग की जिम्मेदारी दी गई थी उस कंपनी ने उपभोक्ताओं से तो पूरी रकम वसूली, लेकिन उसमें से आरटीडीसी को कुछ नहीं दिया।

*(दै.भा., 30.03.16)*

## आवासन मंडल की होगी जांच

आवासन मंडल में हुए भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंपी गई है। मंडल की कार्यशैली पर राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा नाराजगी जताने के बाद अब हाईकोर्ट ने भी गंभीरता दिखाई है।

हाल ही कोर्ट ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच का काम एसीबी को देते हुए कहा है कि आवासन मंडल के भ्रष्टाचार के मामलों की एफआईआर दर्ज कराई जाए।

*(रा.प., 11.03.16)*

# भ्रष्टाचारः सिर्फ रैंकिंग ही सुधरी, हम नहीं

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) के मुताबिक भारत में भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। भ्रष्टाचार कम करने के मामले में भारत 38 अंकों के साथ दुनिया में 76वें पायदान पर है। पिछले साल जारी लिस्ट में भारत 85वें नंबर पर था। रैंकिंग के हिसाब से हम भ्रष्टाचार कम करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें इस बार भी उतने ही नंबर मिलें, जितने पिछली साल मिले थे। यह लिस्ट में देशों की संख्या घटने से हुआ है। पिछली साल लिस्ट में 174 देश थे जबकि इस बार 168 देश ही शामिल हैं।

अर्थात हमारी सिर्फ रैंकिंग ही सुधरी, हम नहीं। हालांकि भ्रष्टाचार कम करने में हम चीन और रूस से आगे हैं।

यह खुलासा टीआई द्वारा जारी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2015 की रिपोर्ट में हुआ है। जारी सूची में 100 में से सबसे ज्यादा 98 अंक डेनमार्क को मिले हैं। वह सबसे कम भ्रष्ट देश है। इसके बाद फिनलैंड 90 व स्वीडन 89 अंकों के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर है। सोमालिया और उत्तर कोरिया 8–8 अंकों के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश हैं। *(दै.भा. एवं रा.प., 28.01.16)*

## मजबूत हो रहा है एसीबी का 'तंत्र'

प्रदेश के सबसे बड़े खान महाघूसकांड का खुलासा करने समेत 25 बड़े घूसखोरों पर लगाम लगाने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का दो करोड़ रुपए के बजट से गोपनीय सत्यापन और इन्वेस्टीगेशन का तंत्र मजबूत हुआ है। इसके बाद हर तथ्य को जुटाकर एसीबी ने बड़े खुलासे किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने एसीबी की 8 रेंज प्राथमिक एवं शिकायत शाखा, अभियोजन शाखा और इन्टेलीजेंस शाखा में 125 अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के पद सृजित करने की प्रक्रिया पूरी की है। एसीबी के कुछ अधिकारियों के पद भी भरे गए हैं।

प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों ने जहां घूसखोरी के लिए तकनीक का उपयोग किया, वहीं एसीबी में रिश्वतखोरी पर शिकंजा कसने के लिए गोपनीय उपकरणों, टेक्नॉलोजी नवीनीकरण, वीडियो डिवाइस और हैण्डी प्रिन्टर समेत अन्य उपकरणों की खरीद की गई। पुलिस आधुनिकरण योजना के तहत भी बजट मिला है और गाड़ियां भी खरीदी गई हैं। इससे एसीबी ने पिछले दिनों हर सबूत के साथ बड़े-बड़े अधिकारियों, दलालों और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार का खुलासा किया।

*(दै.न., 24.01.16)*

**विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां**

| जिला | रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम | कार्यरत विभाग का नाम व पद | रिश्वत में ली राशि (रुपए में) | स्त्रोत |
|---|---|---|---|---|
| झुंझुनूं | संजीव कुमार पूनिया | पटवारी, बिसाऊ, झुंझुनूं | 10,000 | दै.न., 06.01.16 |
| जोधपुर | विपिन कुमार रॉय | अति. महाप्रबंधक, टेलीकॉम प्रोजेक्ट, बीएसएनएल | 50,000 | दै.भा. एवं रा.प., 09.01.16 |
| अलवर | कमलेश मोदी | हैल्पर, एईएन कार्यालय, जलदाय विभाग | 6,000 | दै.भा., 14.01.16 |
| जयपुर | जे.पी.मीणा<br>रघुवीर सिंह गोस्वामी<br>अमित चिराणिया | सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर<br>सहा. सेलटैक्स ऑफीसर, वाणिज्यिक कर विभाग<br>दलाल | 2,00,000 | दै.भा., 21.01.16 |
| हनुमानगढ़ | नेतराम मीणा | पटवारी,चन्द्रपुरी गोसांई भादरा, हनुमानगढ़ | 15,000 | दै.न., 02.02.16 |
| अलवर | रमेश चन्द | यूडीसी, श्रम विभाग कार्यालय, अलवर | 12,000 | रा.प. एवं दै.न., 02.02.16 |
| सीकर | भगीरथ मल यादव | प्रधान, श्री माधोपुर पंचायत समिति, सीकर | 2,35,000 | रा.प. एवं दै.भा., 04.02.16 |
| टोंक | रमेश चौधरी | पटवारी, ग्राम पंचायत मोरभटियान, टोड़ारायसिंह | 6,000 | दै.न., 09.02.16 |
| प्रतापगढ़ | मोती सिंह चौहान<br>हरिराम मीणा<br>राजेश गुर्जर | जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग<br>सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग<br>कम्प्यूटर ऑपरेटर | 2,00,000 | दै.भा. एवं रा.प., 12.02.16 |
| जयपुर | प्रेमचन्द जैन | रीडर, एडीएम-प्रथम कार्यालय, जयपुर कलेक्टरेट | 10,000 | रा.प. एवं दै.न., 12.02.16 |
| जयपुर | पी.के.गोयल | जूलॉजी विभागाध्यक्ष, राजस्थान यूनिवर्सिटी | 20,000 | दै.न., 16.02.16 |
| उदयपुर | मोहन लाल मूंदड़ा<br>लक्ष्मीलाल सोनी | एलडीसी, राजस्थान भू अभिलेखागार विभाग<br>संविदाकर्मी, राजस्थान भू अभिलेखागार विभाग | 1,80,000 | दै.भा.एवं रा.प., 21.02.16 |
| जयपुर | विशाल सिंह<br>राहुल पारीक<br>जगदीश नारायण शर्मा<br>महेन्द्र निर्वाण | जेईएन, प्रथ्वीराज नगर जोन-18 जेडीए, जयपुर<br>तहसीलदार,प्रथ्वीराज नगर जोन-18 जेडीए, जयपुर<br>अमीन, प्रथ्वीराज नगर जोन-18 जेडीए, जयपुर<br>कनिष्ठ लिपिक, प्रथ्वीराज नगर जोन-18 जेडीए | 3,50,000 | रा.प.एवं दै.न., 12.03.16 |
| डूंगरपुर | अशोक राठौड़<br>गणेशलाल भगोरा | विकास अधिकारी, बिछीवाड़ा पंचायत समिति<br>सचिव कम लिपिक, बिछीवाड़ा पंचायत समिति | 10,000 | रा.प., 17.03.16 |
| राजसमंद | डूंगर सिंह | सांगावास ग्राम पंचायत सरपंच विमलादेवी के ससुर | 1,00,000 | दै.भा. एवं दै.न., 29.03.16 |
| दौसा | रामबाबू शर्मा | सेल्समैन, दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति | 50,000 | दै.न.एवं दै.भा., 30.03.16 |

### जैविक खेती पर केन्द्र देगा मदद

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने घोषणा की है कि केन्द्र सरकार जैविक खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपए देगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और कृषि मंडियों को जोड़ने के लिए एक अप्रेल से ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म योजना शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन के तहत परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की है। तीन वर्ष के दौरान 5 लाख एकड़ जैविक खेती विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

*(दै.भा., 20.01.16)*

### मनरेगा में नहीं होगी कोई कटौती

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महात्मा गांधी नरेगा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मनरेगा योजना को ग्रामीण क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए आश्वस्त किया है कि इसमें धन की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आज ही इस योजना को लागू हुए दस साल पूरे हुए हैं और इससे ग्रामीण विकास के कई नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में यह योजना खासी कारगर साबित हो रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं पर अधिक धन खर्च कर सुविधाएं बढ़ाने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने तमाम आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए कहा कि सरकार मनरेगा पर रिकॉर्ड स्तर पर खर्च कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने देगी। *(दै.न., 03.02.16)*

### हुनर से जोड़कर दिलाएंगे रोजगार

केन्द्र सरकार उद्योग और अकादमी की भागीदारी से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड का गठन करेगी। इसके जरिए 3 साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए देशभर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। मनरेगा के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट 38 हजार 500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है।

युवाओं द्वारा लिए गए कौशल ऋण पर 6 फीसदी तक ब्याज में सहायता दी जाएगी। कौशल प्रशिक्षण के लिए 354 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। मनरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूरे करने वाले 86 हजार परिवारों को कौशल प्रशिक्षण देकर पूर्णकालिक रोजगार से जोड़ा जाएगा।

*(दै.भा., 01.03.16, 09.03.16)*

### लागू होगी नई फसल बीमा योजना

केन्द्र सरकार किसानों के हित में अगली खरीफ फसल से नई फसल बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इसमें किसानों को कम से कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। फसल बर्बादी पर किसान को तुरंत 25 फीसदी राशि व 30 से 45 दिन में पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

यह जानकारी केन्द्रीय कृषि व कृषक कल्याण राज्यमंत्री मोहन कुंडारिया ने देते हुए कहा कि वर्तमान में किसानों को 48-60 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन नई पॉलिसी में कम से कम भुगतान करना होगा। इसका भार केन्द्र व राज्य सरकार मिल कर उठाएगी। *(रा.प., 11.01.16)*

### 'स्टैंड अप इंडिया' का होगा शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 अप्रेल को 'स्टैंड अप इंडिया' योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मकसद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिला वर्ग को सस्ता कर्ज देकर उनमें उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना है।

योजना का क्रियान्वयन 1.25 लाख बैंकों की शाखाओं के जरिए किया जाएगा। इसमें बैंक सबसे आसान ब्याज दर पर ऋण देंगे। योजना के तहत निजी क्षेत्र सहित सभी बैंकों की शाखाएं कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा एक महिला उद्यमी को 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक का ऋण सुलभ कराएंगी। *(न.नु., 29.03.16)*

### भामाशाह योजना से मिलेंगे फायदे

अब 154 सरकारी योजनाओं का फायदा भामाशाह प्लेटफॉर्म के जरिये ही दिया जाएगा। ऐसे में सभी सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थियों, पेंशनधारियों, राशन कार्डधारियों व मनरेगा के जॉब कार्डधारियों को भामाशाह प्लेटफॉर्म में सीडिंग कराना जरूरी हो गया है।

सीडिंग के लिए भामाशाह कार्ड संख्या, बैंक खाता नंबर व संबंधित योजना का कार्ड नंबर आपस में जोड़ना है। ताकि भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोड़ने के बाद योजनाओं का फायदा सीधा संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में राशि जमा होकर मिल जाए।

*(दै.भा., 03.01.16)*

## जरूरी है न्यायिक प्रणाली में सुधार

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देर से मिलने वाला न्याय, न्याय नहीं मिलने के बराबर है। उन्होंने इलाहाबाद में हाईकोर्ट की 150 वीं जयंती पर आयोजित समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि न्याय की अवधारणा तभी साकार हो सकती है जब सभी को जल्द न्याय मिले। विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए न्यायपालिका और सरकार का मिलकर काम करना जरूरी है।

मुखर्जी ने न्यायिक प्रणाली में सुधार की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि देश में न्याय व्यवस्था सर्व सुलभ होनी चाहिए। देश में जजों के काफी पद खाली हैं, जिससे मुकदमों को निपटाने में दिक्कतें आ रही हैं। जजों के रिक्त पदों को भरने का काम किया जाएगा ताकि लंबित मुकदमों को निपटाने में मदद मिले। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने भी लंबित मुकदमों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 60 लाख और देश के हाईकोर्ट में 45 लाख मामले लंबित हैं। *(रा.प., 14.03.16)*

# अक्षय ऊर्जा से रोशन होंगे गांव

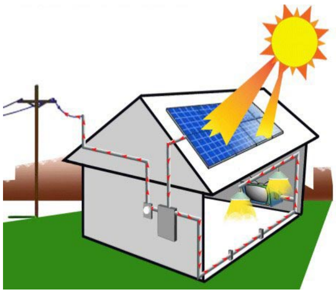

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब सूरज के ताप से बनी बिजली गांव-ढाणियों का अंधेरा दूर करेगी। दरअसल, केन्द्र सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही 'पॉवर फॉर ऑल' की दिशा में काम करना शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य से कार्ययोजना मांगी थी। इस आधार पर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को लागू किया है।

केन्द्र सरकार ने राजस्थान के लिए 2819 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे पॉवर फॉर ऑल के तहत 154 गांव और 9 हजार से अधिक ढाणियों को सोलर सिस्टम के जरिए रोशन किया जाएगा *(रा.प., 25.01.16)*

## सौर ऊर्जा में राज्य सबसे आगे

देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान इस समय सबसे आगे है। जनवरी के मध्य तक देश में कुल 5129.81 मेगावाट की क्षमता विकसित की है। जिसमें राजस्थान की क्षमता 1264.36 मेगावाट की है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, जहां 1024.15 मेगावाट क्षमता विकसित की गई है। मध्यप्रदेश 678.58 मेगावाट की क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर है।

खास बात यह है कि यह जो 5130 मेगावाट की क्षमता सकल रूप से विकसित की गई है, इसमें 1385 मेगावाट की क्षमता चालू वित्त वर्ष के दौरान ही विकसित हुई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 तक देश में एक लाख मेगावाट की क्षमता सौर ऊर्जा के तहत विकसित करने का लक्ष्य रखा है। *(रा.प. एवं न.नु., 16.01.16)*

## उदय योजना से विद्युत प्रबंधन

देश के चार प्रमुख राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों का ऋण पुनर्गठन उदय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इन चार राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व झारखण्ड ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन चार राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों की कुल डिस्कॉम ऋण में 34 फीसदी हिस्सेदारी है।

इस ऋण के एक बड़े हिस्से को राज्य सरकार द्वारा अपने खाते में ले लिया जाएगा। इसका राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा लेकिन वितरण कंपनियों की बैलेंसशीट साफ-सुथरी हो जाएगी। उदय का यह समझौता तीन पक्षीय होगा जिसमें केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय, राज्य सरकार तथा विद्युत वितरण कंपनियां शामिल हैं। *(न.नु., 21.02.16)*

## बिजली कर्ज चुकाएगी सरकार

कर्ज से डूबी राजस्थान की बिजली कंपनियों के 80 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में से 60 हजार करोड़ के कर्ज से आगामी एक-दो माह में राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने इस राशि को केन्द्र की उदय योजना (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) के तहत चुकाने का फैसला किया है।

केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार और बिजली डिस्कॉम कंपनियों के बीच इसका एमओयू भी होगा। इस कर्ज के चुकने के बाद कंपनियों पर 20 हजार करोड़ का ही कर्ज बचेगा। एमओयू में कंपनियों के लिए शर्त होगी कि वे 2019 तक बिजली छीजत को 30 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी करना होगा। हर साल बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव या सिफारिश नियामक आयोग को करनी होगी। *(रा.प., 13.01.16 एवं दै.भा., 28.01.16)*

## औरों के घर भी करेंगे रोशन!

राजस्थान में बिजली उत्पादन की गति अगर योजना मुताबिक रफ्तार से चलती रही तो आगामी कुछ सालों में वो दिन दूर नहीं जब हम हमारे प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों को भी रोशन करने में सक्षम हो सकेंगे। प्रदेश में आगामी पांच सालों में 10 हजार 674 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद जताई गई है। प्रदेश में वर्तमान में 17 हजार 200 मेगावाट उत्पादन सभी प्लांटों को मिलाकर हो रहा है।

आगामी पंचवर्षीय योजना जो कि अगले साल से शुरू होने जा रही है, उसमें प्रदेश के लिए उत्पादन की प्लानिंग से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान बिजली डिस्कॉम के चैयरमैन भास्कर ए. सावंत ने बताया कि कौन से नए प्रोजेक्ट से कितना उत्पादन होगा और कैसे होगा, एनर्जी एसेसमेंट कमेटी इस पर काम कर रही है। *(दै.न., 21.03.16)*

## बिजली छीजत है घाटे का कारण

बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति एवं सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत व डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए.सावंत के साथ विभिन्न सामाजिक व उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद हुआ।

संवाद के दौरान यह उभरकर सामने आया कि प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में बेलगाम बिजली छीजत व बिलिंग में लापरवाही के कारण घाटा 90 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हर साल टेरिफ बढ़ाने के बावजूद ठेकाकर्मियों की ओर से किए जा रहे स्पॉट बिलिंग रैवेन्यू वसूली में मिलीभगत का खेल चल रहा है। वहीं महंगी दरों पर बिजली व मेटेरियल खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। मॉनिटरिंग सिस्टम भी कमजोर है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो और बिजली चोरी रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। *(दै.भा., 23.02.16)*

## देना पड़ता है लेट पैमेंट पर सरचार्ज

उपभोक्ताओं की जागरूकता की कमी के चलते प्रदेश के तीनों डिस्कॉम बिना किसी मशक्कत के हर साल करोड़ों रुपए का फटका दे रहे हैं। डिस्कॉम भी यही चाहता है कि लोग समय पर बिल नहीं भरे। क्योंकि, नियत तिथि के बाद जमा होने वाले बिलों पर लेट पैमेंट सरचार्ज के रूप में उसे उपभोक्ताओं से हर साल 500 करोड़ से भी ज्यादा राशि ठाले बैठे मिल रही है।

यानि, जरा सी देर उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रही है और डिस्कॉम का खजाना भर रही है। बिजली मामलों के जानकारों का कहना है कि उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित कर डिस्कॉम बिना किसी खर्च के इस व्यवस्था में सुधार ला सकता है। लेकिन प्रोत्साहन योजना तो दूर की बात डिस्कॉम उपभोक्ताओं को बिल ही समय पर नहीं पहुंचा पाता। *(रा.प., 06.03.16)*

### पेयजल स्त्रोतों का होगा सर्वेक्षण

भूजल में लगातार गिरावट आने के कारण जर्जर हालत में चल रहे पेयजल स्त्रोतों का अब बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें हर जल स्त्रोत की मौजूदा स्थिति और उसके सुधार के प्रावधान शामिल होंगे। जलदाय विभाग ने इसके लिए उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर व जयपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों व जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया है।

इस बेसलाइन सर्वे में आपणी योजना वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। सर्वे में मौजूदा पेयजल सप्लाई के स्त्रोत और बरसात के दौरान आसपास के पानी की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। सर्वे का मकसद संबंधित क्षेत्रों में भविष्य के लिए पेयजल आपूर्ति का सिस्टम व इंटरकनेक्टिविटी विकसित किया जाना है। *(दै.न., 20.03.16)*

### पानी सहेजने पर पंचायतें होगी पुरस्कृत

वर्षा जल के संचय को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री किरण माहेश्वरी ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम पुरस्कार के तौर पर पांच लाख रुपए, द्वितीय को तीन लाख रुपए और तृतीय को दो लाख रुपए देने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया है, वहीं सतही पेयजल स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में भूजल की स्थिति में सुधार भी हुआ है। पहले राज्य में 223 डार्कजोन थे जो अब 204 रह गए हैं। सेफ ब्लॉक्स की संख्या भी 25 से बढ़ कर 44 हो गई है। *(रा.प., 30.03.16)*

### रोजाना दो लाख का पानी चोरी

फील्ड अभियंताओं की लापरवाही के चलते जलदाय विभाग को रोजाना दो लाख रुपए का चूना लग रहा है। शहर में पेयजल आपूर्ति व राजस्व वसूली के आंकड़े इसका खुलासा कर रहे हैं कि जगह-जगह लीकेज और हजारों अवैध कनेक्शनों के चलते उपभोक्ताओं के हिस्से का 30 फीसदी पानी चोरी जा रहा है।

इसमें 10 फीसदी तकनीकी छीजत मान ली जाए तो भी 20 फीसदी पानी की सीधी चपत लग रही है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती रही है।

जलदाय मंत्री द्वारा अवैध कनेक्शनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन विभाग अवैध कनेक्शनों पर लगाम लगाने के प्रति गंभीर नहीं है। *(रा.प., 27.02.16)*

### पुरानी पेयजल लाइनों ने बढ़ाई छीजत

शहर की अधिकांश आबादी जहां पुरानी जर्जर पाइप लाइनों से पानी पी रही है, वहीं पेयजल सप्लाई के दौरान इन जर्जर पेयजल लाइनों से हो रही पानी की छीजत विभाग के लिए कोढ़ में खाज बनी हुई है। चारदीवारी सहित अधिकांश स्थानों पर यह लाइनें वर्षो पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं।

इससे शहर में कुल पानी सप्लाई का 35 प्रतिशत पानी लीकेज, अवैध कनेक्शन और अन्य कारणों से छीजत में चला जाता है। कई इलाकों में यह जर्जर लाइनें सीवर लाइन के नजदीक से जा रही हैं, जिससे पेयजल लाइन के लीकेज से पेयजल में सीवर का पानी मिलकर दूषित और जानलेवा हो रहा है। जलदाय विभाग को इन पुरानी लाइनों को बदलकर पानी की बर्बादी और दूषित पानी की सप्लाई को रोकने की जरूरत है। *(दै.न., 11.02.16)*

### इस साल नहीं होगा पानी महंगा

प्रदेश में एक अप्रेल से बढ़ने वाली पेयजल की दरें अभी नहीं बढ़ेंगी। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री किरण माहेश्वरी ने राज्य विधानसभा में अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए यह घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने 17 साल बाद नवंबर 2015 में पेयजल की दरें बढ़ाई थीं। पेयजल में दस फीसदी वृद्धि एक अप्रेल से होनी प्रस्तावित थी। लेकिन इसे अब अप्रेल 2017 तक टाल दिया गया है। बीसलपुर पेयजल के फेज द्वितीय की घोषणा करते हुए मंत्री ने जानकारी दी कि जयपुर के समस्त नगर निगम क्षेत्र को बीसलपुर से जोड़ना प्रस्तावित है। *(रा.प., 30.03.16)*

### मेंटीनेंस चार्ज से मिलेगी मुक्ति

पेयजल उपभोक्ताओं के भले ही पानी के मीटर खराब पड़े हो, लेकिन लंबे समय से उपभोक्ताओं से मीटर मेंटीनेंस के नाम पर 20 रुपए प्रति माह वसूले जा रहे हैं। अब राज्य सरकार इसे खत्म करने की तैयारी कर रही है। इसका मसौदा फाइनल कर लिया गया है।

विभागीय स्वीकृति के बाद इस पर अंतिम मुहर वित्त विभाग की लगेगी। इस फैसले के बाद पेयजल उपभोक्ताओं को यह राहत मिलेगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद मीटर खरीद से लेकर उसके मेंटिनेंस की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं की ही होगी। *(दै.न., 04.03.16)*

## जल स्वावलम्बन अभियान में जुटें

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि 'मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान' राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। राज्य में पानी की कमी की समस्या के समाधान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसकी सफलता के लिए प्रदेश के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, कॉरपोरेट्स एवं मीडिया संस्थानों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी व सहयोग आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सभी जिलों के लिए 350 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं तथा प्रथम चरण में प्रदेश के 3000 गांवों का चयन किया गया है। अगले तीन सालों में हर साल छह हजार गांवों का इस मिशन में सम्मिलित किया जाएगा। चार वर्ष की अवधि तक चलने वाले इस अभियान के तहत जल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन से जुड़े कार्य किए जाएंगे। *(दै.न., 04.01.16, 24.01.16)*

### 'पालनहार' ने की बच्चों की नैया पार

विधवाओं, परित्यक्ताओं के बच्चों तथा अनाथ बच्चों के अच्छे दिन आने की उम्मीद है। क्योंकि, तीन सालों से अटकी हुई पालनहार योजना का पैसा बच्चों को मिलने लगा है।

योजना में प्रदेशभर में करीब एक लाख 50 हजार बच्चों के आवेदन हैं। इनमें से 25 हजार बच्चों को योजना के तहत सहायता राशि दी जा चुकी है। आवेदकों को कई महीनों का भुगतान अब एक साथ मिल रहा है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस माह में सभी बच्चों के खातों में सहायता राशि पहुंच जाएगी। योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पांच साल के बच्चों को 500 रुपए प्रतिमाह व स्कूल में प्रवेश के बाद एक हजार रुपए प्रतिमाह व साल में एक बार दो हजार रुपए की सहायता दी जाती है। *(रा.प., 06.01.16)*

### महिलाओं के लिए खोला पिटारा

इस बार प्रदेश का बजट महिला दिवस के मौके पर रखा गया। इसी दिन वसुंधरा राजे का जन्म दिन भी था। शायद इसीलिए महिलाओं को जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कई योजनाओं के जरिए प्रोत्साहित किया गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री राजश्री योजना का ऐलान किया गया है। जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक बालिकाओं को 50 हजार रुपए तक का लाभ मिल सकेगा। लेकिन उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ना आवश्यक होगा।

प्रदेश में 30 हजार नए स्वयं सहायता समूहों का गठन कर करीब 4 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 5.75 लाख बीपीएल परिवार की महिलाओं के खातों में 2000 रुपए जमा कराए जाएंगे। उद्योगों में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए भू-रूपान्तरण छूट को 50 से बढ़ाकर 100 फीसदी किया गया है। महिला युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। बालिका संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। पालनहार योजना के लिए बजट में 171 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

*(रा.प.एवं दै.न., 09.03.16)*

### बच्चों की बनेगी स्वास्थ्य कुंडली

प्रदेशभर में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके लिए मोबाइल चिकित्सकों की टीमें लगाई जा रही हैं। इसमें डेढ़ माह से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चों की स्वास्थ्य कुंडली बनाई जाएगी।

बच्चों में बीमारी मिलने पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उनका इलाज कराया जाएगा। किसी बच्चे में गंभीर बीमारी मिलने पर उसकी जांच व इलाज के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से इस कार्य की शुरुआत कर दी गई है। *(दै.न., 04.01.16)*

### एएनएम देंगी योजनाओं की जानकारी

चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने सभी एएनएम को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आरोग्य राजस्थान अभियान के बारे में अपने क्षेत्र में जन-जन तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने प्रदेश की सभी एएनएम से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सीधे संवाद करते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक गर्भवती माता को पूर्ण जांच और प्रसव पूर्व सेवाएं सुगमता से सुलभ होनी चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराकर ही माताओं और शिशुओं को अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि 15 फरवरी के बाद राज्य स्तरीय आकस्मिक जांच दल भिजवाकर एएनएम के आरसीएच रजिस्टर की जांच कराई जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

*(दै.न., 10.01.16)*

### श्रमिकों के लिए शिव शक्ति योजना

श्रम विभाग ने जनवरी 2016 से शिव शक्ति योजना शुरू की है। योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा व विवाह के लिए 55 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

पहले श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए विवाह पंजीकरण योजना के तहत 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता था। इसमें बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए खर्च का कोई प्रावधान नहीं था। शिव शक्ति योजना में बेटियों की उच्च शिक्षा के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। *(रा.प., 07.02.16)*

## राधेश्याम स्वयं सहायता समूह राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित

नाबार्ड के सहयोग से 'कट्स' मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा गठित राधेश्याम स्वयं सहायता समूह को वर्ष 2014-15 के लिए राज्य स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयपुर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में नाबार्ड जयपुर की मुख्य महाप्रबंधक सरीता अरोरा से समूह की अध्यक्ष बदामबाई व देउबाई गाड़ी लौहार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

अहिंसा नगर गाड़ी लौहार बस्ती (औछड़ी) में वर्ष 2008 में गठित इस समूह की महिलाओं ने बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रतापनगर शाखा से सस्ते ब्याज पर पांच लाख रुपए का ऋण लेकर लोहे के औजार बनाने की हम्मबर मशीन लगाई है और अपने पुश्तैनी कारोबार को बढ़ाया है। इससे उनकी आमदनी में अच्छा इजाफा हुआ है। इस समूह से एक सौ से भी ज्यादा गाड़ी लौहार परिवार की महिलाएं जुड़ी हुई है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं।

## जन स्वास्थ्य

### माताओं को नहीं मिल रहा उचित पोषण

राज्य में हर साल जन्म लेने वाले करीब 18 लाख शिशुओं में से पहले ही साल 80 हजार की जीवन डोर टूट जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण उचित पोषण और स्वास्थ्य की सही देखरेख नहीं होना बताया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (एसआरएस) के अनुसार अभी प्रदेश में प्रति हजार जीवित जन्म पर 47 बच्चे दम तोड़ देते हैं।

हालात माताओं की मौत के मामले में भी अच्छे नहीं है। अभी प्रदेश में हर साल करीब 4300 महिलाएं प्रसव के दौरान या उसके बाद दम तोड़ देती है। फिलहाल प्रदेश में यह अनुपात प्रति एक लाख पर 244 महिलाओं की मौत का है। नवजात मौत के कारणों में जिला अस्पतालों में नर्सरी, एनआईसीयू न होना व स्वास्थ्य केन्द्रों पर बीमारियों से निपटने की व्यवस्था न होना है।

स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक मां को उचित पोषण नहीं मिलने के कारण बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। जन्म के समय बच्चे का औसत वजन 2.5 किलो होना चाहिए लेकिन 38 फीसदी बच्चों का वजन जन्म के समय इससे काफी कम होता है। *(रा.प., 20.03.16)*

### सेहत का खयाल – बजट पर एक नजर

केन्द्रीय बजट में स्वस्थ महिला व सुरक्षित परिवार पर खास ध्यान दिया गया है। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के जरिए प्रत्येक परिवार को सालाना एक लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा देने का वादा किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को इसमें 30 हजार रुपए की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। जरूरतों को देखते हुए हर जिले में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डायलिसिस सुविधा की शुरुआत की जाएगी।

राजस्थान के बजट में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को खास तवज्जो दी गई है। ई-हैल्थ कार्ड को भामाशाह बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 13.10 करोड़ रुपए की लागत से अस्पतालों का भवन निर्माण किया जाएगा। छोटे अस्पतालों का रूप बदला जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मजबूती के लिए 1718.12 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में कई नए उपकरण व साधन मुहैया कराए जाएंगे। आयुर्वेदिक पद्धति को भी खास तौर से बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में दिव्यांगों का भी खयाल रखा गया है।

*(रा.प.एवं दै.न., 01.03.16, 09.03.16)*

## सड़क सुरक्षा

### गांवों तक सड़कें, पहुंच होगी आसान

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है। राज्यों के हिस्से मिलाकर यह राशि 27 हजार करोड़ रुपए होगी। वर्ष 2019 तक 2.23 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण से 65 हजार गांव सड़कों से जुड़ेंगे। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

राजस्थान के बजट के मुताबिक प्रदेश में 8 हजार 803 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 250-350 तक की आबादी की 1468 बस्तियां सड़कों से जुड़ेंगी। इसके लिए 1618 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 250 से 499 तक की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 142.85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

*(रा.प. एवं दै.न., 09.03.16)*

## पर्यावरण

### जयपुर में खतरे से 4 गुना ज्यादा प्रदूषण

राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर के प्रदूषण विभाग द्वारा मुहैया कराए गए 1 से 15 जनवरी के बीच के आंकड़ों को देखें तो उसमें काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शहर में रोज करीब 15 लाख गाडियां सड़कों पर दौड़ती है जो दिन-रात हवा को जहरीला बना रही है।

शहर के प्रमुख स्थानों पर खतरनाक पार्टिकुलेटेड मैटर (पीएम)10 का जो स्तर इस माह की शुरुआत में था, वह उससे कहीं अधिक बढ़ गया है। वहीं सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मानक से तो काफी नीचे हैं लेकिन उसकी दर बढ़ोतरी की ओर है। प्रदूषण के खतरनाक स्थिति में पहुंच जाने पर स्थानीय प्रशासन का चुप्पी ओढ़े रहना इस संकट को और बढ़ाएगा। जयपुर में खतरनाक पार्टिकुलेटेड मैटर 10 मानक से तीन से चार गुना तक अधिक है। यह हवा में 100 माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर तक मान्य है। जबकि ज्यादातर इलाकों में किसी भी सूरत में 200 माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर से कम नहीं है। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित जांच यंत्र में इसे 13 जनवरी को सर्वाधिक 415 माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर तक पाया गया। अजमेरी गेट पर यह 8 जनवरी को 254 माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर था। *(रा.प., 16.01.16)*

## वित्तीय सेवाएं

### वित्तीय रूप से 76 फीसदी लोग साक्षर नहीं

भारत में 76 फीसदी लोग वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं। उन्हें मुद्रास्फीति, ब्याज दर, चक्रवर्ती ब्याज दर आदि का ज्ञान व अर्थ पता नहीं है। स्टैंडर्ड एंड पूअर रेटिंग्स सर्विसेज ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे में यह जानकारी दी गई है। सर्वे में कहा गया है कि एशिया में सिंगापुर में सबसे ज्यादा यानी 59 प्रतिशत लोग वित्तीय रूप से साक्षर हैं। हांगकांग और जापान में 43 प्रतिशत और चीन के 28 फीसदी वयस्क वित्तीय साक्षरता रखते हैं। अमेरिका के 57 प्रतिशत और ब्रिटेन के 67 प्रतिशत वयस्क वित्तीय रूप से साक्षर हैं।

वैश्विक स्तर पर करीब 66 फीसदी वयस्क वित्तीय साक्षरता नहीं रखते। करीब-करीब हर देश में महिलाओं व पुरुषों में वित्तीय ज्ञान की जानकारी में अंतर है। वैश्विक स्तर पर 65 फीसदी पुरुष वित्तीय साक्षरता नहीं रखते हैं, जबकि महिलाओं की यह संख्या 70 फीसदी है। भारत में यह अन्तर ज्यादा है। भारत में 73 फीसदी पुरुष वित्तीय साक्षरता नहीं रखते जबकि महिलाओं की संख्या 80 फीसदी है। सर्वे में 140 देशों के करीब डेढ़ लाख लोगों से पूछताछ की गई। जिसमें बचत, ब्याज दर, ऋण, जोखिम, मुद्रास्फीति के बारे में सवाल किए गए। *(न.नु., 15.01.16)*

## श्रेष्ठ एन.जी.ओ. का पुरस्कार

उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए 'कट्स' को जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड़ द्वारा 24 फरवरी, 2016 को जयपुर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में श्रेष्ठ स्वयं सेवी संस्थाओं की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।

यह पुरस्कार अरूण चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार एवं सुमन शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान महिला आयोग द्वारा प्रदान किया गया जिसे कट्स महामंत्री प्रदीप महता ने ग्रहण किया।

**उपभोक्ता फैसले**

### बिजली मीटर बदलने में की देरी: अब देना होगा हर्जाना

जयपुर निवासी भूराराम ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(जेवीवीएनएल) के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में परिवाद दायर किया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उसने जेवीवीएनएल के सहायक अभियंता के यहां अपने घरेलू बिजली कनेक्शन के खराब हुए मीटर को बदलने के लिए 30 जून 2009 को प्रार्थना-पत्र पेश किया था। लेकिन उनके बिजली के मीटर को बदलने के बजाय उसे औसत उपभोग के आधार पर गलत बिजली के बिल भेजे गए। उन्होंने कई बार कार्यालय में जाकर उनसे संपर्क भी किया। लेकिन उनकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और पांच महीने की देरी के बाद उनका विद्युत मीटर बदला गया।

मामले की सुनवाई पर जिला उपभोक्ता मंच ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को सेवा का दोषी माना। मंच ने कहा कि मीटर बदलने में देरी करना जेवीवीएनएल की लापरवाही और अकर्मण्यता पूर्ण कार्यशैली है। मंच ने निगम की ओर से दी गई दलील कि उपभोक्ता द्वारा निर्धारित मीटर टेस्टिंग शुल्क नहीं जमा कराया गया को नकारते हुए कहा कि शुल्क जमा नहीं कराने की आड़ में पांच महीने बीतने पर भी बिजली मीटर को नहीं बदलना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। मंच ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता भूराराम को क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 हजार रुपए का हर्जाना अदा करें।

*(दै.भा., 09.02.16)*

### खराब बीज से नुकसान किसान को मिलेगा हर्जाना

जयपुर स्थित गांव फुलेरा निवासी किसान कैशाराम चौधरी ने महाराष्ट्र हाईब्रीड कॉरपोरेशन व कंपनी के जयपुर प्रतिनिधि के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने परिवादी कंपनी के डीलर से वर्ष 2001 में 2200 रुपए के प्याज के बीज खरीदे थे। बीज खरीदते समय डीलर ने उन्हें भरोसा दिया था कि बीज अच्छी गुणवत्ता के हैं। उन्होंने इन बीजों की खेत में बुवाई की और दिसम्बर 2001 में रोपाई का काम कराया। लेकिन अप्रैल 2001 में फसल तैयार होने लगी तो उसमें फूल निकल आए, जिससे उनकी 80 फीसदी फसल खराब हो गई। उन्होंने मंच को बताया कि इससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने परिवादी कंपनी के जयपुर प्रतिनिधि को कम गुणवत्ता युक्त बीज देने का दोषी माना, जिससे किसान कैशाराम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। मंच ने बीज निर्माता कंपनी महाराष्ट्र हाईब्रीड कॉरपोरेशन व कंपनी के जयपुर प्रतिनिधि को आदेश दिया कि वह किसान कैशाराम चौधरी को हुए आर्थिक नुकसान की एवज में एक लाख रुपए का हर्जाना अदा करें। इसके अलावा मंच ने फैसले में यह भी कहा कि परिवादी कंपनी से मुकदमा खर्च की राशि 10 हजार रुपए भी लेने का हकदार है।

*(दै.भा., 08.03.16)*

### ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

**ग्राहक सुविधा केन्द्र**
**कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)**, डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

**स्त्रोत:** रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति

**पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी**, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।